भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3128

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

20 फाल्गुन, 1947 (शक)

सॉफ्टवेयर उत्पाद संबंधी राष्ट्रीय नीति

3128. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सॉफ्टवेयर उत्पाद संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2019 (एनपीएसपी) के अंतर्गत 'फ्यूचरस्किल्स प्राइम', 'एनजीआईएस', 'समृद्ध', 'जेनेसिस', 'टाइड 2.0', 'डिजी-सपने' और 'भाषिणी' जैसे कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त निर्दिष्ट कार्यक्रमों के लाभार्थियों की विशेषकर आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले सहित कुल संख्या कार्यक्रम-वार, राज्य-वार और जिला-वार कितनी है;
(ग) गत पांच वर्षों के दौरान पूरे देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले सहित एनपीएसपी को लागू करने के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि कार्यक्रम-वार, राज्य-वार और जिला-वार कितनी है;
(घ) देश भर में प्रस्तावित, चयनित और वर्तमान में कार्यशील उद्यमिता केंद्रों की सूची का राज्य-वार और आंध्र प्रदेश में जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने एनपीएसपी के अंतर्गत कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कार्यकलाप/अभियान चलाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति (एनपीएसपी), 2019 ने भारत के आईटी क्षेत्र को सेवा-आधारित उद्योग से उत्पाद-संचालित डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस नीति का उद्देश्य भारत को सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना, बौद्धिक संपदा (आईपी) निर्माण को बढ़ावा देना और घरेलू मांग और सॉफ्टवेयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है।

एन.पी.एस.पी. के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं:

पहल	संक्षिप्त	स्थिति
फ्यूचरस्किल्स प्राइम	एआर/वीआर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आदि सहित नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में आईटी पेशेवरों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग	फ्यूचरस्किल्स प्राइम पोर्टल (https://futureskillsprime.in) पर 27.53 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 17.2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन /प्रशिक्षण लिया है। आंध्र प्रदेश राज्य में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3.29 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया है/प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनमें नेल्लोर जिले के 9,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके लिए 436.87 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
जेनेसिस	इसका उद्देश्य पूरे भारत में युवाओं के नेतृत्व वाले 10,000 स्टार्टअप की पहचान करना, उनका विकास करना और उन्हें सशक्त बनाना है	अब तक 500 से अधिक एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (ईआईआर) लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश में इनमें से 29 ईआईआर को सहायता प्रदान की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 54.5 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
भाषिनी	राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) डिजिटल पहुंच हेतु भाषा की बाधा को दूर करने के लिए।	इस कार्यक्रम का बजट परिव्यय 495.51 करोड़ रुपये है, जिसमें से अब तक 464.27 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। भाषिनी प्लेटफॉर्म (https://bhashini.gov.in/) वर्तमान में 36 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, 350 एआई भाषा मॉडल होस्ट करता है, और प्रति दिन औसतन 13 मिलियन से अधिक निष्कर्षों के साथ 4 बिलियन से अधिक निष्कर्षों को संसाधित किया है।
डिजी-सपने	पूर्वोत्तर में स्टार्टअप्स को बड़े उद्यमों में विकसित होने और सामाजिक प्रभाव वाले तकनीकी समाधान तैयार करने में सहायता प्रदान करके उनका सहयोग करना।	पूर्वोत्तर क्षेत्र से चयनित 36 स्टार्टअप को तीन साल की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें प्रत्येक समूह में 12 स्टार्टअप का चयन किया गया है। इस योजना का बजटीय परिव्यय 5.76 करोड़ रुपये है।

समृद्ध	एक्सीलरेटर के माध्यम से स्केलिंग के लिए स्टार्टअप्स तक बाजार पहुंच और निवेशकों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है	16 राज्यों में फैले 43 शीर्ष एक्सेलरेटरों को 373 स्टार्टअपों के विकास में सहयोग देने के लिए चुना गया था, जिनमें से 241 स्टार्टअपों ने मैचिंग निवेश राशि हासिल कर ली है। इसके अलावा, 99 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और कार्यक्रम 31 जनवरी, 2026 को सम्पन्न हुआ।
टाइड 2.0	इनक्यूबेटरों में वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता के माध्यम से प्रौद्योगिकी उद्यमिता को बढ़ावा देता है।	51 इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से 1,800 से अधिक स्टार्टअप को सहायता दी गई है, जिसमें कुल 224 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कार्यक्रम 31 जनवरी 2026 को सम्पन्न हुआ।
एनजीआईएस (नेक्स्ट जेनरेशन इनक्यूबेशन स्कीम)	टियर-II और टियर-III शहरों में तकनीकी स्टार्टअप्स को समावेशी नवाचार विकास को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करता है।	686 स्टार्टअप को सहायता दी गई है, जिनमें से 180 को सीड फंडिंग प्राप्त हुई और 359 को स्टाइपेंड सहायता प्राप्त हुई। कुल 67.84 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और कार्यक्रम 25 सितंबर, 2025 को संपन्न हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य में 133 स्टार्टअप को सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के 24 उद्यमिता केंद्र (सीओई) देश भर में कार्य कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में, उद्योग 4.0 पर एक सीओई, जिसका नाम कल्पतरु है, विशाखापत्तनम में कार्य कर रहा है।

सरकार ने सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति, 2019 के अंतर्गत कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता और आउटरीच पहल की हैं।

इनमें कार्यशालाएं, विशेषज्ञ वार्ता और वेबिनार, नवाचार और हैकथॉन चुनौतियां, उद्योग निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग, आधिकारिक पोर्टलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में भागीदारी और टियर- II और टियर- III शहरों में लक्षित आउटरीच शामिल हैं।

देश भर में जागरूकता और भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के लिए ये प्रयास जारी हैं।

******